देशवासी ही मेरे वारिस : मोदी

प्रधानमंत्री का दावा, आंबेडकर नहीं होते तो नेहरू एससी और एसटी को आरक्षण नहीं मिलने देते

अर्चिस मोहन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर नहीं होते तो पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) को आरक्षण नहीं मिलने देते। उन्होंने यह भी कहा कि उनका कोई वारिस नहीं है। उनके पास कोई विरासत या संपत्ति भी नहीं है। देशवासी ही उनके सब कुछ हैं।

बिहार के महाराजगंज में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानामंत्री ने कहा, 'गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने वारिसों को कुछ देने की इच्छा रखता है। मोदी ऐसा इंसान है, जिसकी कोई विरासत नहीं है। मेरे लिए तो आप ही मेरी विरासत हैं। आप ही मेरे वारिस हैं। मेरा और कोई वारिस नहीं है।' दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस बयान के एक दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी की यह टिप्पणी आई है, जिसमें केजरीवाल ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी 75 साल की उम्र में सेवानिवृत्त हो जाएंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनके बाद प्रधानमंत्री बनेंगे।

पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में रैली को संबोधित करते हुए एससी, एसटी के आरक्षण के सवाल पर प्रधानमंत्री ने दावा किया, 'नेहरू आरक्षण के खिलाफ थे। उन्होंने तो मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इसका विरोध किया था। नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक इस परिवार के जितने प्रधानमंत्री हुए, सबने ओबीसी आरक्षण का विरोध किया।' उन्होंने कहा, 'कांग्रेस के पास एक ही वोट बैंक आज बचा है और वे उसे खुश करने के लिए एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण धर्म के आधार पर आपसे छीनकर 'वोट जिहाद' वालों को देना चाहते हैं। संविधान इसकी इजाजत नहीं देता, इसलिए ये संविधान बदलना चाहते हैं।' प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों पर यह झूठ फैलाने का आरोप लगाया कि भाजपा यदि फिर भारी बहुमत से सत्ता में आई तो वह संविधान में संशोधन कर आरक्षण समाप्त कर देगी।

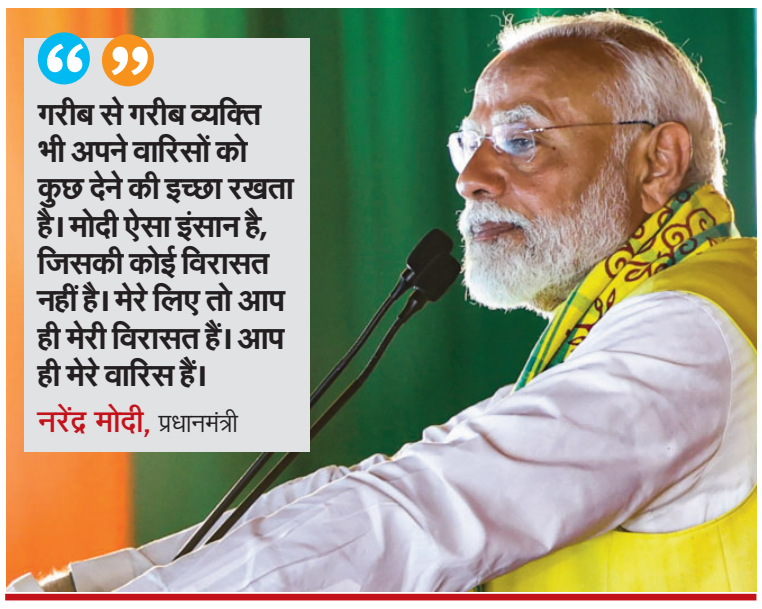

> गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने वारिसों को कुछ देने की इच्छा रखता है। मोदी ऐसा इंसान है, जिसकी कोई विरासत नहीं है। मेरे लिए तो आप ही मेरी विरासत हैं। आप ही मेरे वारिस हैं।
>
> **नरेंद्र मोदी,** प्रधानमंत्री

उन्होंने कहा, 'राजग ने पहले दलित बेटे को और फिर हमारे देश की आदिवासी बेटी को संविधान के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद पर बिठाया। हमारी सरकार ही है, जिसने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया।' मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव पर परोक्ष निशाना साधा और कहा, 'जो लोग चांदी की चम्मच लेकर पैदा होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि मेहनत क्या होती है। मैंने सुना है कि यहां कोई घूम-घूम कर कह रहा है कि चार जून के बाद मोदी 'बेड रेस्ट' पर जाएंगे। मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, मैं तो यही कामना करता हूं कि मोदी तो क्या देश के किसी भी नागरिक के जीवन में 'बेड रेस्ट' की नौबत नहीं आनी चाहिए।'

दूसरी ओर, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जमशेदपुर में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आदिवासी विरोधी हैं। उन्होंने आदिवासियों के सबसे बड़े नेता हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया है। सोरेन की पत्नी कल्पना मोदी को झांसी की रानी के रूप में चुनौती पेश कर रही हैं। किसी भी अदालत ने हेमंत सोरेन या अरविंद केजरीवाल को दोषी नहीं पाया है।

उन्होंने कहा कि यदि आप लोग कमल के निशान (भाजपा का चुनाव चिह्न) पर बटन दबाएंगे तो सोरेन जेल में रहेंगे। यह झारखंड और आदिवासी समुदाय के साथ बड़ा धोखा होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर नहीं बुलाया गया, क्योंकि वह आदिवासी थीं। यदि आज आदिवासी चुप रहे तो उनका उत्पीड़न होता रहेगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यदि भाजपा 400 सीटों के साथ दोबारा सत्ता में आई तो वह एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण समाप्त कर देगी।

'गलत' समय में एक मुलाकात ने आप को संकट में डाला

आदिति फडणीस

किसी ने नहीं सोचा था कि एक छोटी सी बात का इतना बड़ा बखेड़ा बन जाएगा। एक राज्य सभा सदस्य अपनी पार्टी के अध्यक्ष के साथ मुलाकात के लिए महज समय मांगना चाहती थीं, मगर यह मामला आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व के बीच एक ऐसी राजनीतिक जंग में तब्दील हो गया जहां एक ओर पार्टी अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल एवं वरिष्ठ नेता आतिशी हैं तो दूसरी ओर दिल्ली से राज्य सभा सदस्य स्वाति मालीवाल एवं अन्य नेता हैं।

दिल्ली विधान सभा में विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) भी इस चुनावी मौसम में इस मुद्दे को भुनाने के लिए कूद पड़ी है और परोक्ष रूप से कांग्रेस को भी इसमें घसीटा जा रहा है। आम आदमी पार्टी में शुरुआती दिनों से जुड़े कुछ लोगों का मानना है कि यह पार्टी नेतृत्व में खींचतान का मामला है।

मालीवाल ने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत इंडिया अगेंस्ट करप्शन (आईएसी) में स्वयंसेवकों के संयोजक के तौर पर की थी। उस आंदोलन का नेतृत्व अन्ना हजारे ने किया था। वह उसकी मुख्य सदस्य थीं। वह उन लोगों में से भी थीं जिन्होंने उस आंदोलन को एक राजनीतिक दल में बदलने का समर्थन किया था।

आईएसी कोर कमिटी की सदस्य रह चुकीं मैराथन धावक और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता सुनीता गोदारा कहती हैं कि आईएसी के दौरान उनके कार्य और निर्भया मामले के दौरान लोगों को जुटाने की काबिलियत को देखते हुए स्वाति को दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) का अध्यक्ष बनाया गया था। गोदारा उन खिलाड़ियों में से एक थीं जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में भ्रष्टाचार से जुड़े मसले पर दायर की गई याचिका में अन्य बड़े खिलाड़ियों को साथ लिया था। बाद में उन्होंने आप पार्टी की शुरुआत होने पर खुद को अलग कर लिया।

गोदारा कहती हैं, 'आप की स्थापना में मालीवाल की बड़ी भूमिका रही है। इसलिए जब वह 13 मई को मुख्यमंत्री से बगैर समय लिए मिलने के लिए उनके आवास पहुंची तो मिलने से रोके जाने पर उन्हें बुरा लगा होगा।'

मालीवाल ने कहा था कि मुख्यमंत्री के निजी सचिव विभव कुमार ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इसलिए कुमार के खिलाफ गंभीर आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया गया है। कुमार अभी हिरासत में है। दिल्ली में कानून-व्यवस्था केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। मालीवाल ने यह भी आरोप लगाया है कि आप ने सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ की है और असली फुटेज में उन पर हमला होते दिख सकता है। आप का कहना है कि मालीवाल बगैर समय लिए पहुंच गईं और उन्हें लगा था कि केजरीवाल उनसे अकेले मिलेंगे।

> मालीवाल ने अपने करियर की शुरुआत इंडिया अगेंस्ट करप्शन में स्वयंसेवकों के संयोजक के तौर पर की थी

आप की महाराष्ट्र इकाई की प्रमुख प्रीति शर्मा मेनन ने कहा, 'हम विभव को आंदोलन के दिनों से जानते हैं। वह ऐसे काम कर ही नहीं सकते हैं जो उन पर आरोप लगाए गए हैं।' उन्होंने कहा, 'स्वाति जी को पार्टी ने सब कुछ दिया है। उन्हें दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, राज्य सभा भेजा गया। वह अमेरिका में थीं और जब लोक सभा चुनावों के लिए अभियान शुरू हुआ तो वह काफी निष्क्रिय थीं। वह अरविंद जी पर हमले की साजिश रच रही थीं। वह सुबह 8.30 बजे अरविंद जी के आवास चली गईं क्योंकि उन्हें पता था कि विभव और अन्य लोग थोड़ी देर से आते हैं और उन्हें अरविंद जी अकेले मिल जाएंगे। यह प्रभु श्री हनुमान की कृपा थी कि विभव वहां मौजूद थे और उन्होंने ही अरविंद जी पर हमला होने से रोक दिया।'

मेनन ने कहा कि भाजपा ने केजरीवाल को एक मामले में उलझाने के अभियान के तहत मालीवाल को भेजा था मगर वह उस साजिश में विफल रहीं।

हालांकि, भाजपा का कहना है कि यह पूरी तरह बकवास है। दिल्ली भाजपा के नेता सुधांशु मित्तल ने कहा, ' भाजपा इतनी मजबूत नहीं है कि किसी पीड़िता को बरगला सके और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सके। ये विरोधाभास भी स्पष्ट है। अपने पहले बयान में ही मालीवाल ने अपने ऊपर हुए हमले के लिए अरविंद केजरीवाल को ही जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन, लिखित शिकायत में उनका नाम गायब है। हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप ने अपने को खुद फंसाया है।'

उन्होंने कहा, 'यह पूरी तरह से बेशर्मी है। हमने आप के सांसद संजय सिंह को यह कहते सुना है कि विभव कुमार ने जो किया वह गलत है और उसकी जांच की जानी चाहिए। इसके लिए सिंह ने खास तौर पर संवाददाता सम्मेलन भी किया था। फिर भी दिल्ली सरकार की मंत्री और आप की वरिष्ठ नेत्री आतिशी सहित पार्टी के अन्य नेता अब यह कह रहे हैं कि मालीवाल ने पहले बदतमीजी की थी। हम किस पर विश्वास करें। पीड़ित पर या अपराधी पर। मालीवाल पीड़िता हैं फिर भी आप नेता अपराधी के साथ हैं।'

आप के सूत्रों ने कहा कि इस पूरे मसले पर संजय सिंह का हस्तक्षेप जल्दबाजी में लिए गए फैसले के कारण हुई गलती थी और उन्होंने स्वीकार किया कि इससे उनका मामला कमजोर हुआ है।

गोदारा का कहना है कि केजरीवाल ऐसे लोगों को नापसंद करते हैं जो उनसे ज्यादा निपुण, अधिक बुद्धिमान और ज्यादा पढ़े-लिखे हों। वह उन्हें खतरा मानते हैं। गोदारा का मानना है कि मालीवाल की प्रतिक्रिया भी किसी अन्य कारण से हो सकती है। कहा जा रहा है कि केजरीवाल ने मालीवाल को राज्य सभा से इस्तीफा देने के लिए कहा (वैसे उनका कार्यकाल 2030 में समाप्त होगा) ताकि उनकी जगह एक वकील को राज्य सभा सदस्य बनाया जा सके, जो केजरीवाल और उनके सहयोगियों के सभी कानूनी मसले संभाल रहे हैं। केजरीवाल की पसंद कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी हो सकते हैं, जो हाल ही में हिमाचल प्रदेश से राज्य सभा चुनाव हार गए थे।

मगर सिंघवी ने इसे अफवाह और अटकलबाजी बताकर खारिज कर दिया। सिंघवी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड से कहा, 'यह इतना हास्यास्पद है कि इस पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं बनती है। एक टीवी चैनल के तथाकथित एंकर ने ऐसी आधारहीन अटकलें लगाई और फिर अन्य लोगों ने भी इसे लपक लिया क्योंकि ऐसी बातें सभी को पसंद आती हैं। मेरे लिए इतना कुछ किया गया, और मुझसे ही नहीं पूछा गया और न ही मुझे इस बारे में कोई जानकारी है।'

दिल्ली में 25 मई को लोक सभा चुनाव के लिए मतदान होना है। केजरीवाल के 2 जून को जेल जाने से पहले ये एक ऐसा मसला है जिस पर आप को कुछ करना ही होगा क्योंकि इससे नेतृत्व संकट भी मंडराने लगा है।

अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री

'चुप्पी महिला सुरक्षा पर उनके रुख को बताती है'

दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के सक्सेना ने मंगलवार को कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सदस्य के साथ कथित मारपीट पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 'गहरी चुप्पी महिलाओं की सुरक्षा पर उनके रुख के बारे में बहुत कुछ बोलती है' और कहा कि मुख्यमंत्री को इस घटना पर 'टाल-मटोल' और 'पैंतरेबाजी' नहीं करनी चाहिए। 'आप' ने पलटवार करते हुए कहा कि उपराज्यपाल का पत्र साबित करता है कि 'मालीवाल भाजपा के इशारे पर काम कर रही हैं।' राज निवास ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक बयान जारी किया है, जिसमें सक्सेना ने कहा कि दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है और इसे 'तार्किक निष्कर्ष' पर पहुंचाया जाएगा।

बिहार के पिछड़ेपन के लिए कांग्रेस जिम्मेदार : निर्मला

अर्चिस मोहन

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बिहार और पूर्वी भारत के औद्योगिक पिछड़ेपन के लिए साल 1952 से लेकर 1991-92 तक की कांग्रेस सरकार की माल ढुलाई समानीकरण नीति को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा बिहार के औद्योगीकरण को बढ़ावा देने और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए किए जा रहे कार्यों पर विस्तार से जानकारी दी। पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में पूछे गए सवाल पर कि क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, इस पर सीतारमण ने कहा, 'इसको लेकर बात चली है कि इसे दिया जाना चाहिए, लेकिन जब निर्णय होगा तब होगा।' वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार में बदलाव की दिशा में एक प्रमुख पहल प्रधानमंत्री का विशेष पैकेज है। इसकी घोषणा साल 2015 में की गई थी और इसके तहत राज्य के विकास के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपये देने का ऐलान किया गया था।

सीतारमण ने कहा कि साल 2004 से 2014 तक वित्त आयोग के कर हस्तांतरण फॉर्मूले के अनुसार बिहार को 2.04 लाख करोड़ रुपये मिले मगर मोदी सरकार के दस वर्षों में (साल 2014 से 2024 तक) ही प्रदेश को 7.05 लाख करोड़ रुपये मिले हैं। यह 3.5 गुना की वृद्धि है। उन्होंने कहा कि साल 2014 से 2024 के बीच बिहार को अब तक 2.81 लाख करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है, जो साल 2004 से 2014 के मिलने 75,213 करोड़ रुपये की तुलना में 3.7 गुना ज्यादा है।

वित्त मंत्री ने बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की विरासत को बचाने में केंद्र के प्रयासों के बारे में भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि फिलहाल केंद्रीय मंत्रिमंडल में 60 फीसदी मंत्री अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से ताल्लुक रखते हैं और सरकारी योजनाओं के अधिकतर लाभार्थी भी इन्हीं श्रेणियों के हैं। उन्होंने कहा, 'मोदी सरकार ने बिहार के सम्मानित दलित नेता बाबू जगजीवन राम की जयंती पर स्टैंड-अप इंडिया योजना की शुरुआती कर उनकी विरासत का सम्मान किया।' उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया और उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सीताराम केसरी को याद करते हुए कहा कि सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए कांग्रेसियों ने केसरी का अपमान करते हुए पद से हटा दिया था।

इंडियन बिग फोर के लिए अपील

रुचिका चित्रवंशी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि बिहार के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) इंडियन बिग फोर फर्म यानी चार विशाल कंपनियां स्थापित करने और वैश्विक ग्राहक तलाशने को चुनौती के रूप में ले। पटना में आईसीएआई के साथ चर्चा में सीतारमण ने कहा कि वे विकसित भारत 2047 के लिए 100 दिनों के एजेंडे के तहत उनसे वादा करें कि इस तरह की विशाल फर्म स्थापित करने की दिशा में काम शुरू करेंगे। वित्त मंत्री ने कहा, ऐसा क्यों है कि बड़ी संख्या में हमारे देश के बिग फोर फर्म में हिस्सेदार और नेतृत्वकर्ता की भूमिका में होते हैं, लेकिन ऐसी बिग फोर फर्म भारत में नहीं बनाते। इस दिशा में बिहार से नेतृत्व क्षमता दिखाने का आह्वान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि बिग फोर में से एक फर्म कहीं ओर से नहीं, बल्कि बिहारी दिमाग से निकलनी चाहिए।

चांदनी चौक : सरकार से अपेक्षाएं अनेक

निवेदिता मुखर्जी

तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। इसके बावजूद पुरानी दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में रौनक कम नहीं है। करीब 400 साल पहले सफेद मार्बल और लाल बलुआ पत्थर से बनी देश की सबसे मशहूर मस्जिद की सड़क के दूसरी ओर मामूली सी चाय की दुकान है। चाय विक्रेता रईस कहते हैं कि अभी उन्होंने तय नहीं किया है कि इस बार किसे वोट डालेंगे। इतना कह वह बर्तन चूल्हे पर चढ़ाकर चाय बनाने में व्यस्त हो जाते हैं।

शनिवार की तपती दुपहरी में किनारी बाजार, दरीबा कलां और नई सड़क जैसी तंग लेकिन मशहूर गलियों में रिक्शा, दुपहिया और पैदल चलने वालों की इस कदर भीड़ कि निकलना मुश्किल। इसी दिन राजधानी दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की रैलियां हुईं, लेकिन रईस को इसकी कोई परवाह नहीं। जब उनसे पूछा गया कि अब तक इलाके में कितनी रैलियां और सभाएं हो चुकी हैं तो वह तपाक से कहते हैं, 'हमारे पास कोई नेता वोट मांगने नहीं आया।'

पास ही मोहम्मद इरफान अपनी किराने की छोटी सी दुकान पर बैठे भुट्टा चबा रहे हैं। वह कम ग्राहकी से परेशान हैं। कहते हैं, 'कारोबार ही नहीं है।' इरफान ने चांदनी चौक से भाजपा उम्मीदवार और कन्फैडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के महासचिव प्रवीन खंडेलवाल के बारे में सुना है। चुनाव के दौरान उभरे हिंदू-मुस्लिम मुद्दे पर उनके विचार क्या हैं? इस पर इरफान जवाब देते हुए कहते हैं, 'ये राजनीतिक मुद्दे हैं। आम लोगों को इनसे कुछ लेना-देना नहीं।' मालूम हो कि कारोबार के अड्डे चांदनी चौक में बड़ी आबादी मुसलमानों की है।

यहां से हम जामा मस्जिद के पास ही स्थित मशहूर रेस्टोरेंट करीम्स पर पहुंचे। वर्ष 1913 में स्थापित होटल और रेस्टोरेंट श्रृंखला करीम्स के निदेशक जैनुल आबिदीन भी इस बात से सहमत दिखे कि कारोबार बहुत मंदा है। जैन साहब के नाम से मशहूर होटल कारोबारी कहते हैं, 'सैलानी आ ही नहीं रहे। ऊपर से गर्मी ने बुरा हाल कर रखा है।' जैन साहब के अनुसार, 'वैश्विक स्तर पर बदली भूराजनीतिक परिस्थितियों के कारण विदेशी पर्यटकों की संख्या कम हुई है, वहीं महंगाई बढ़ने के कारण स्थानीय ग्राहक घर से बाहर खाना खाने का कार्यक्रम टाल देते हैं।'

बातचीत के दौरान जब बात हिंदू-मुस्लिम के मुद्दे पर आती है तो वह कहते हैं, 'हमारे यहां 80 से 90 प्रतिशत ग्राहक गैर मुस्लिम होते हैं।' जब हम वहां से रिक्शा में बैठकर लाल किले की ओर जाने लगते हैं, तो रास्ते में जैन मंदिर, गुरुद्वारा शीश गंज, सेंट्रल बैप्टिस्ट चर्च और फतेहपुरी मस्जिद पड़ती है। इस एक सड़क पर अलग-अलग धर्मों के इतने सारे धार्मिक स्थल हिंदुस्तान की सच्ची धर्मनिरपेक्षता की तस्वीर पेश करते हैं। लेकिन, सड़क किनारे अपने कारोबार जमाए बैठे व्यापारी सतर्क हैं और वे अपनी चुनावी पसंद के बारे में कुछ नहीं बताते। उन्हें इस बात का डर सताता है कि कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त करने पर उन पर किसी राजनीतिक दल से जुड़े होने का ठप्पा लग जाएगा, जिस कारण उन्हें अपने कारोबार में इसका सीधा नुकसान हो सकता है। बहुत कुरेदने पर वे धीरे से कहते हैं, 'जिसकी सत्ता होती है, हम उसे ही सलाम ठोकते हैं।'

> चांदनी चौक में क्या व्यापारियों के मुद्दे हल होंगे?

फतेहपुरी चौक पर कुलचा किंग के मालिक तनुज गंभीर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि आज विश्व में भारत की रेटिंग बहुत अच्छी हो गई है। मौजूदा सरकार की यह सबसे बड़ी उपलिब्ध है। बात बेरोजगारी पर चली तो कहने लगे, 'बेरोजगारी तो पहले भी खूब थी। मोदी जी कोई जादूगर नहीं हैं। ऐसी समस्याओं के निदान के लिए उन्हें करीब 15 साल और चाहिए।' कुछ दुकानें छोड़कर थोड़ी दूरी पर शॉल और अन्य ऊनी कपड़े बेचने वाले मोहम्मद दानिश आने वाली सरकार से कर में छूट और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की ख्वाहिश जाहिर करते हैं। वह यह भी कहते हैं कि भाजपा दिल्ली की सात में कम से कम पांच सीट जीतेगी। पिछले लोक सभा चुनाव में भाजपा ने सातों सीट जीती थीं।

टाउन हॉल के पास एक ज्वैलरी दुकान चलाने वाले पवन अग्रवाल पूरी तरह आश्वस्त हैं कि भाजपा क्लीन स्वीप करेगी। वह कहते हैं कि रोजगार देना सरकार का काम नहीं है। अपने बाजारों, स्ट्रीट फूड, इस्लामिक आर्किटेक्चर और अब हेरिटेज वॉक के लिए प्रसिद्ध चांदनी चौक में हम एक बार फिर रिक्शा में सवार होते हैं। हमें नई सड़क से होते हुए मेट्रो स्टेशन पहुंचना है, लेकिन होलसेलर का गढ़ कही जाने वाली नई सड़क पर हमारा सामना भयंकर जाम से होता है।

हम कनॉट प्लेस पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। यहां सड़कों पर दूसरा नजारा था। साइकिल और रिक्शा की जगह चमचमाती कारें दौड़ रही थीं। सड़क किनारे अव्यवस्थित खाने-पीने की दुकानों की जगह यहां शानदार रेस्टोरेंट और बार वीकऐंड पर ग्राहकों के लिए तैयार थे। वैसे, जनप्रतिनिधियों से पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली के व्यापारियों की अपेक्षाएं एक जैसी हैं। जनपथ पर मॉडर्न स्टोर्स के संचालक अजय सूद चाहते हैं कि कर में कमी होनी चाहिए। वह पश्चिमी दिल्ली में रहते हैं। वहीं उनका वोट है। वह मानते हैं कि चुनाव में भाजपा का पलड़ा भारी है, क्योंकि विपक्ष में कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं है। वह कहते हैं कि बेरोजगारी और महंगाई ऐसे मुद्दे हैं, जो पिछले 70 वर्षों से हैं। म्यूजिक और कॉस्मेटिक्स की दुकान चलाने वाले एक व्यापारी मौजूदा सरकार से काफी निराश नजर आते हैं। वह नहीं चाहते कि यह सरकार दोबारा आए। यहां घूमने-फिरने आए कारोबारी इस संवाददाता को सलाह देते हैं कि किसी गरीब से बात करिए। आपको पता चल जाएगा कि उनकी दशा क्या है। यहां आइसक्रीम विक्रेता इंद्रजीत कहते हैं, 'आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि ग्राहक के हाथ में पैसा ही नहीं है।' चॉकलेट और फल आदि बेचने वाले एक दुकानदार ने भी इसी तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त की।

बदलाव की जरूरत पर चर्चा है, लेकिन जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर भाजपा की पहल का सवाल आता हे तो सब दुकानदार उसकी सराहना करते हैं। एक दुकानदार ने कहा, 'इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता।' दूसरी ओर खंडेलवाल एमेजॉन और फ्लिपकार्ट की मालिकाना हक वाली वालमार्ट जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ एक दशक से मोर्चा खोले हुए हैं ताकि स्थानीय व्यापारियों को नुकसान से बचाया जा सके। स्थानीय कारोबारी और एमएसएमई इस सरकार की प्राथमिकता में रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी नहीं बने थे, तो फरवरी 2014 में उन्होंने कैट के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया था। सिरी फोर्ट में आयोजित इस सम्मेलन में मोदी ने छोटे कारोबारियों से अपने कामकाज में तकनीक का सहारा लेने की अपील की थी, ताकि उत्पादकता और बिक्री बढ़ाई जा सके।

चांदनी चौक सीट पर कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल से मुकाबले में उतरे खंडेलवाल की प्राथमिकता में क्या व्यापारियों के मुद्दे अभी भी होंगे? कम से कम उनके सहयोगियों को तो उनसे ऐसी उम्मीद लगी ही है।

भाजपा प्रत्याशी की आयोग से पुनर्विचार की अपील

चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रचार करने पर 24 घंटे की पाबंदी लगाने के कुछ घंटों बाद तमलुक लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा कि उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर निर्णय पर पुनर्विचार करने की अपील की है। एक स्थानीय भाषा के समाचार चैनल से बातचीत में कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि यदि आयोग अपने फैसले पर विचार नहीं करता है तो वह अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे।

उन्होंने कहा, 'मैंने ईसीआई को लिखा है कि वह अपने फैसले पर विचार करे। यदि आदेश पर विचार नहीं किया गया तो मैं आदेश रद्द कराने के लिए उचित समय पर अदालत का रुख करूंगा।' **भाषा**

www.bankofbaroda.in
बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
निविदा सूचना
बैंक ऑफ़ बड़ौदा 5 वर्ष की अवधि के लिए केंद्रीकृत लॉग प्रबंधन सोल्युशन (सीएलएमएस) की आपूर्ति, क्रियान्वयन और रखरखाव के लिए सेवा प्रदाता के चयन हेतु प्रस्ताव आमंत्रित करता है। विस्तृत विवरण बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in के निविदा खंड और गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल पर उपलब्ध है।
अन्य सूचना, यदि कोई हो, को बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर निविदा खंड में जारी किया जाएगा। प्रस्ताव को अंतिम रूप से प्रस्तुत करने से पहले बोलीकर्ता इसे अवश्य देख लें।
प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 12 जून, 2024 है।
स्थान : मुंबई
दिनांक : 22.05.2024
मुख्य महाप्रबंधक (आईटी)
21/24-25

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक !
punjab national bank ...the name you can BANK upon !
सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग,
प्र.का., 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001
ई-मेल: eprocurement@pnb.co.in दूरभाष : 011-23724596
निविदा सूचना
पंजाब नेशनल बैंक एप्लिकेशन सुरक्षा परीक्षण समाधान (एसएएसटी और डीएएसटी) की खरीद और कार्यान्वयन के चयन के लिए पात्र बोलीदाताओं से GeM पोर्टल (सरकारी ई मार्केटप्लेस) के माध्यम से ऑनलाइन बोलियां (तकनीकी और वाणिज्यिक दोनों) आमंत्रित करता है।
इच्छुक बोलीदाता विवरण के लिए वेबसाइट https://gem.gov.in पर जा सकते हैं।
ऑनलाइन बोली जमा करने की अंतिम तिथि 12-06-2024 तक है।
मुख्य प्रबंधक